

अहमदनगर जिले के सेवा केन्द्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Kavita Tomar*

School of Social Science, Devi Ahilya University, Indore

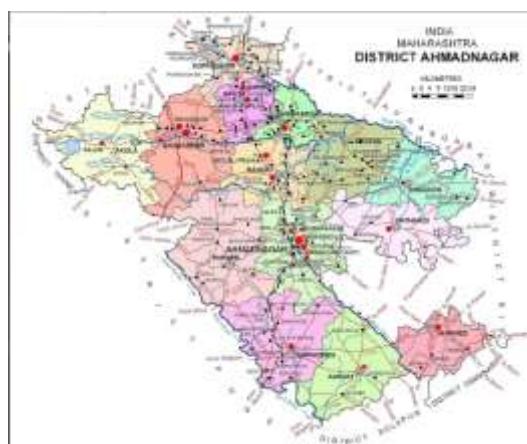
शोध सारांश- किसी भी प्रदेश में ग्रामीण व नगरिया क्षेत्रों के लिए सुक्षम स्तर विकास करने हेतु एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता होती है। अच्छी रणनीति के लिए संपूर्ण प्रदेश में किस स्तर पर कौन सी आर्थिक गतिविधि एवं सामाजिक सुविधाएं हैं यह जात होना आवश्यक है। यह सर्व विदित तथ्य है की नगरिया क्षेत्रों में सुविधाएं होती हैं परंतु ग्रामीण जनसंख्या सामाजिक- आर्थिक सुविधाओं के लिए नगरों के लिए दूरी तय करती है। ग्रामीण जनसंख्या को ग्रामीण स्तर पर सामाजिक आर्थिक सुविधाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा केन्द्रों की पहचान तथा कार्य आधारी (Threshold population) जनसंख्या वाले क्षेत्रों में नए सेवा केन्द्रों की स्थापना एक आवश्यकता बन गई है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां 70% जनसंख्या ग्रामीण हैं वहां यह सेवा केन्द्र प्रादेशिक विषमता को कम करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शब्द कुंजी: : सेवा केन्द्र, केंद्रीयतामान, श्रेणी, पदानुक्रम, विकास पोलर, ग्रामीण सेवा केन्द्र

X

परिचय

भारत को मुख्यत चार भौतिक भागों में विभाजित किया गया है व्रहद हिमालय, उत्तरी समतल मैदान, दक्कन पठार और तटवर्ती तथा द्रवीपीय भाग। अहमदनगर जिला भौतिक रूप से दक्कन पठार का भाग है। यह जिला महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अहमदनगर जिला आंशिक रूप से ऊपरी गोदावरी बेसिन में और आंशिक रूप से भीमा बेसिन में महाराष्ट्र राज्य में कुछ हद तक केंद्रीय स्थिति में है। यह जिला $18^{\circ}10'$ उत्तरी अक्षांश से $20^{\circ}00'$ उत्तरी अक्षांश तक हैं। इसका देशांतरीय विस्तार $73^{\circ}30'$ से $75^{\circ}37'$ तक है। जिला आकार में अनियमित है और 200 किलोमीटर की लंबाई और 220 किलोमीटर की चैडाई के साथ तिरछी क्रॉस के समान है। जनसंख्या 350859 है। इस जिलो को 14 तहसीलों में विभाजित किया गया है। इन 14 तहसीलों में 1587 गाँव हैं जिसमें से 3 अनिवासित हैं।



उद्देश्य

1. जिले के सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम को जात करना
2. सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता जात करना
3. ग्रामणी सेवा केन्द्रों की पहचान करना

शोध प्राविधि व साहित्यक पुनरावलोकन

इस शोध में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है जिन्हें अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक, प्रकाशित शोध पत्र तथा शिवाजी विश्वविद्यालय की पीएचडी थिसिस और ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से लिया गया है आंकड़ों के विश्लेषण के लिए कार्यों की संख्या, कार्यों की विविधता और कार्यों के स्तर के आधार पर उनको (सेवा केन्द्रों) को मान दिया गया तथा डेविस विधि द्वारा सेवा केंद्र की केन्द्रीयता श्रेणी का निर्धारण किया गया

विकास पोलर सिद्धांत (Growth polar theory)

सेवा केंद्र / वृद्धि केंद्र (service centre) अवधारणा का मुख्य सैद्धांतिक आधार विकास पोलर (growth polar) सिद्धांत / वृद्धि मॉडल है। पैरोक्स कि इस अवधारणा के अनुसार विकास कुछ महत्वपूर्ण पोलर (growth polar) से शुरू होकर विभिन्न माध्यमों से सभी दिशाओं में फैलाया जा सकता है। 'पैरोक्स' की यह अवधारणा "भौगोलिक स्थान" के साथ जुड़ी है उन्होंने एक ऐसे आर्थिक स्थान की परिकल्पना की है जो विकास का एक बड़ा पोलर (growth polar) हो, वह आधुनिक औद्योगिक उपक्रम एवं सभी सुविधाएं रखता हो तथा यह सुविधाये अग्र (forward) एवं पश्च (backward) संयोजन के माध्यम से आसपास के सभी क्षेत्रों में फैलती है। 1960 के दशक में विकसित एवं विकासशील देशों की व्यवहारिक कार्य नीतियां विकास पोलर (growth polar) अवधारणा जिसे विकास पोलर (growth polar) रणनीति कहते थे पर आधारित थी। 1970 के दशक के उत्तरार्ध तक विकास पोलर (growth polar) रणनीतिया कम से कम 28 विकसित एवं विकासशील देशों में लागू हुई जैसे कि ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कोलंबिया घाना, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, यूके व भारत आदि। विकास पोलर (growth polar) सिद्धांत/वृद्धि पोलर (growth polar) सिद्धांत को 1980 के दशक में बड़े पैमाने पर असफलता मिली क्योंकि समाज में यह असंतोष बढ़ रहा था कि पिछड़े क्षेत्रों में नई आर्थिक प्रगति को प्रेरित करने की अपने उद्देश्य में "विकास पोलर (growth polar) नीतियां" विफल रही हैं प्राय यह देखा गया कि संतुलित प्रादेशिक विकास के बावजूद विकास पोलर (growth polar) सिद्धांत प्रादेशिक विषमता को जन्म देता है।

Satohar & Todtling (1977) ने अपने अध्ययन में पाया कि "विकास पोलर (growth polar) रणनीति" विकास के अपने प्रभाव क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्र) तक नहीं पहुंचा सकती। अतः इसका स्थानीय प्रसार प्रभाव कमजोर है। भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए "नीचे से ऊपर इष्टिकोण / सैद्धांतिक उपागम / प्रारंभिक बिंदु उपागम / (bottom up approach) को अपनाना होगा। लेकिन विकास पोलर (growth polar) सिद्धांत नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण के माध्यम से "ऊपर से नीचे उपागम (bottom up approach) पर जोर देता है। इसीलिए इस मॉडल से ग्रामीण विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रदेश में संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 'क्रिस्टलर' का "केंद्रीय स्थान सिद्धांत, विकास पोलर (growth polar) सिद्धांत" से बेहतर प्रतीत होता है।

क्रिस्टलर मॉडल सिद्धांत

क्रिस्टलर का सिद्धांत निगमनात्मक उपागम पर आधारित है। यह सिद्धांत कस्बों के आकार, उनकी संख्या तथा वितरण की व्याख्या करता है। यह वितरण पदानुक्रम सिद्धांत पर आधारित है। 'क्रिस्टलर' के सिद्धांत को वास्तविक नियोजन के प्रयोग में लाया जा सकता है। यह सिद्धांत ग्रामीण सेवा केंद्र, सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह सिद्धांत दो चीजों पर आधारित है-

1. कार्य आधारी जनसंख्या
2. वस्तुओं की श्रेणी

'क्रिस्टलर' की अवधारणा समरूपी क्षेत्र पर आधारित है अर्थात जनसंख्या का समान रूप से वितरण हो साथ ही संसाधन, परिवहन, सुविधाएं भी समान रूप से प्रदेश में वितरित हो, ऐसा क्षेत्र ढूँढा कठिन है। 'क्रिस्टलर' का मॉडल नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूरा करता है। इस सिद्धांत से यह पता चलता है कि बस्तियों के वितरण प्रतिरूप में केंद्रीय स्थानों में पदानुक्रम है अर्थात वह पदानुक्रमित है। उच्च पदानुक्रम के केंद्रीय स्थान, निम्न पदानुक्रम के केंद्रीय स्थानों से संख्या में कम है तथा अधिक स्थान को धेर हुए हैं। किसी भी सेवा केंद्र का आसपास की बस्तियों पर प्रभाव उस सेवा केंद्र में उपलब्ध वस्तुओं और सुविधाओं की संख्या व विविधता से पड़ता है। एक केंद्रीय स्थान सैद्धांतिक रूप से किसी दिए गए क्षेत्रीय प्रदेश में सतत रूप से अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए कार्य सेवा देकर केंद्रीयता का लाभ प्राप्त करता है।

ग्रामीण सेवा केन्द्रों की पहचान

किसी भी गांव को ग्रामीण सेवा केंद्र होने के लिए 7000 जनसंख्या होनी चाहिए और कम से कम दो केंद्रीय कार्य निम्न क्रम के कार्यों के समूह से होने चाहिए.

(अ) शैक्षिक सुविधाएं

1. प्राइमरी स्कूल
2. सेकेंडरी स्कूल
3. जूनियर स्कूल
4. सीनियर कॉलेज

(ब) मेडिकल सुविधाएं

1. डिस्पेंसरी
2. परिवार नियोजन केंद्र
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
4. मातृत्व एवं बाल कल्याण केंद्र
5. अस्पताल

(स) बाजार सुविधाएं

1. साप्ताहिक बाजार

(द) संचार सुविधाएं

1. पोस्ट ऑफिस

(य) प्रशासनिक सुविधाएं

1. पंचायत समिति
2. तहसील ऑफिस
3. कलेक्टर ऑफिस

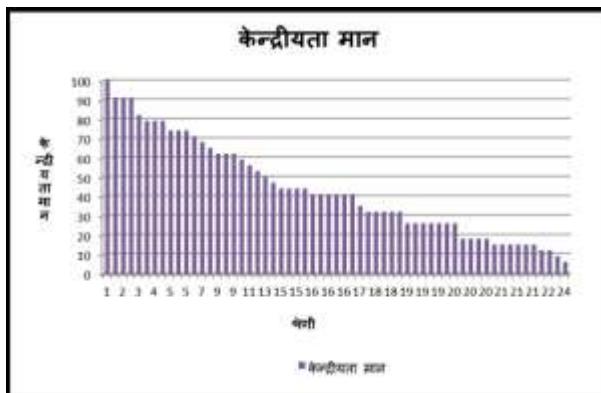
(र) वित्त सुविधाएं

1. भारतीय स्टेट बैंक

उपरोक्त सुविधाओं के आधार पर डेविस की विधि का उपयोग करते हुए अध्ययन क्षेत्र में सेवा केंद्रों का केंद्रीय मान व सेवा केंद्रों का पदानुक्रम जात किया है

सारणी-1

क्रमांक	सेवा केंद्र का नाम	केन्द्रीयता मान	श्रेणी
1	अहमदनगर	100	1
2	करजात	91	2
3	रहरी	91	2
4	श्रीरामपुर	91	2
5	सोनड़	82	3
6	जामखेड़	79	4
7	सगमनेर	79	4
8	शेवगाव	79	4
9	नवासा	74	5
10	पारनेर	74	5
11	अकोला	74	5
12	कोपरखांव	71	6
13	रसीन	68	7
14	पठावी	65	8
15	खोलर	62	9
16	श्रीगोदा	62	9
17	बेलापुर	62	9
18	लोनी	59	10
19	राजुर	56	11
20	रथा	53	12
21	खरदा	50	13
22	देओलाली प्रवारा	47	14
23	निघोज	44	15
24	मिराज गाँव	44	15
25	पुन्ताम्बा	44	15
26	लोनी	44	15
27	तकलिमन	41	16
28	बेलचंदी	41	16
29	बोधेगाव	41	16
30	चंदा	41	16
31	वारी	41	16
32	कोतुल	41	16
33	शिर्डी	35	17
34	कसित	32	18
35	सकुर	32	18
36	घोदेगांव	32	18
37	ज्यूर	32	18
38	ताकालिमिया	32	18



अध्ययन क्षेत्र में शोधकर्ता को 59 अधिवास ऐसे मिले हैं जो सेवा केंद्र होने की अर्हता रखते हैं इन 59 बस्तियों का केंद्रीय मान डेविस विधि द्वारा प्राप्त किया गया है जो कम और उच्च मूल्य के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। सारणी-1 में प्रथम 6 कोटी के शहर जिला व तहसील है जिसमें अहमदनगर (100), करजात (91), रहरी (91), श्रीरामपुर (91), सोनई (82), और जामखेड (79) हैं। अध्ययन क्षेत्र में 59 केंद्रीय स्थानों का निरीक्षण किया गया है जिनमें से 44 केंद्र स्थान अहमदनगर के उत्तर में स्थित हैं अर्थात कुल सेवा केन्द्रों का 75% भाग अहमदनगर के उत्तर में स्थित है। पूरे अध्ययन क्षेत्र में 4543159 जनसंख्या है ए जिसका 64% भाग अर्थात 2570154 जनसंख्या अहमदनगर के उत्तरी जिले में निवास करती है ए वहाँ दूसरी ओर सेवा केन्द्रों का 75% भाग उत्तरी जिले में है। इन आंकड़ों के अवलोकन से जात होता है कि जनसंख्या बढ़ने पर सेवा केन्द्रों की संख्या बढ़ती है पूरे अध्ययन क्षेत्र में अहमदनगर शहर प्रथम कोटि का सेवा केंद्र है जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं और कार्य रखता है यह प्रदेश का प्रमुख सेवा केंद्र बना हुआ है जिसमें कई शिक्षा व चिकित्सा संस्थान हैं इसी आधार पर इसका केंद्रीयता मान 100 और श्रेणी स्तर-1 है यह केंद्रीयता मान व श्रेणी कार्यों की संख्या के आधार पर डेविस की विधि द्वारा निकाली गई है इसी प्रकार अन्य 58 सेवा केन्द्रों का केंद्रीयता मान व श्रेणी निकाली गई है।

निष्कर्ष

सेवा केन्द्रों की केंद्रीयता व पदानुक्रम कार्यों की संख्या, कार्यों की विविधता और कार्यों के स्तर पर निर्भर करती है। उपरोक्त अध्ययन में हमने सेवा केन्द्रों की केंद्रीयता व पदानुक्रम को जात किया है ए साथ ही ग्रामीण सेवा केंद्र की पहचान की है जो ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं साथ ही ग्रामीणों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जिससे ग्रामीण वासियों का जीवन सुविधाजनक बन रहा है जो उन्हें नगरों तक दूरी तय करने के लिए विवश नहीं करता। इस तरह ग्रामीण

सेवा केंद्र ग्रामीण वासियों के जीवन में एक अलग और अहम भूमिका पूर्ण करते हैं।

संदर्भ सूची

1. Gharpur V.T. (2005) "Spatial Organization And Hierarchical Ordering Of Agero Service In Panchaganga Basin: An Existing Expected Perspective" Published Ph.D theses, Shiva ji uni. Kolhapur, Raj publishing house, Jaipur
2. Gharpur V.T. & Panvar C.T. (1987), "Centrality And Hierarchy Of Agro Service Centre In Panchaganga Basin" The Geographer Vol. XXXIV No. 1 P.P. 55-59
3. Kulkarni, suyog praksh (2004), "Distribution Of Settlements in North Ahmednagar District: A Geographical Analysis" Dissertation. P.P. 55-59
4. Mohit. B. M. & Choudhry. D. H. (2011), "Geographical Study Of Centrality Rank and Hierarchy Of Market Centres in Beed District", Journal of Research and Development Vol.I (issue-8), P.P. 24-30
5. Dr. Thakur S. A.(2011). "The Centrality of Market in Sindhudurg district." Journal of Research and Development Vol.1 (issue-7) P.P 49-53
6. Singh, R.Y. (1998), "Geographical of Settlement", Rawat Publication New Delhi p.p 280-330
7. Singh, S.B. (1977),"Distribution Centrality And Hierarchy Of Rural Central places In Sultanpur District U.P. India", National Geographical Journal Of India, Part 3 and Vol XX111 P.P. 185-194

Corresponding Author

Kavita Tomar*

School of Social Science, Devi Ahilya University, Indore

tomarkavita517@gmail.com